



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629]

No. 1629]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2008/कार्तिक 28, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2008/KARTIKA 28, 1930

वित्त मंत्रालय

( वित्तीय सेवाएं विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 2695(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2008 है ।

(2) यह सजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. खंड 2 का संशोधन.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), के खंड 2 में,—

(i) उप-खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(गक) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;’

(ii) उप-खंड (ज) में, “मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “पदाभिहित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ।

3. खंड 3 का संशोधन.—उक्त स्कीम के खंड 3 के उप-खंड (2) में,—

(क) मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन से अन्यून कर्मचारियों के ऐसे पैनल से, जो प्रतिनिधि संघ द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे पैनल की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रतिनिधि संघ के अनुरोध पर, स्वविवेकानुसार, बैंक के लिए कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने के लिए अवधि को 15 दिन के लिए और बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रतिनिधि संघ कर्मचारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करने में असफल रहता है और ऊपर यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसको नहीं भेजता है तो बैंक केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और बैंक से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, बैंक के प्रबंधन से अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों का पैनल अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी प्रतिनिधि संघ के रूप में बैंक के किसी संघ, परिसंघ, संगम के सत्यापन या प्रमाणीकरण में विलंब होने की संभावना है और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी कर्मचारी को जो कोई कर्मकार है उस बैंक के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।”;

(ख) उपमद (ii) का लोप किया जाएगा ।

4. प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन किया जाना- उक्त स्कीम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

**‘पहली अनुसूची**  
**[खंड 2(ज) देखिए]**

**विषय : राष्ट्रीयकृत बैंको में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया ।**

1. पदधारी कर्मकार निदेशकों के कार्यकाल के अवसान से एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार बैंक के प्रबंधन को, प्रतिनिधि संघ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बैंक के कर्मकार कर्मचारी से संबंधित संघ की सदस्यता की पदसंख्या का सत्यापन करने की सलाह देगी । बैंक का प्रबंधन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक के स्तर के किसी अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो पूर्वोक्त सत्यापन करेगा । संघ, परिसंघ या संगम की सदस्यता का सत्यापन चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित सुसंगत वर्ष के मार्च मास के लिए कर्मकार के वेतन से की गई कटौती के आधार पर किया जाना है ।

2. उपाबंध 1 के अनुसार, यथास्थिति, आंकड़ों या ब्यौरों के साथ सूची (सूचियाँ) संलग्न होगी जिनमें बैंक के कर्मकारों के प्रत्येक संघ के सदस्यों के नाम, उसका पदनाम और उसके कार्यकरण की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया जाएगा, ऐसी सूची (सूचियाँ) को पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार की सलाह की प्राप्ति पर तुरंत संकलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, इस सर्त के अधीन रहते हुए, बैंक के किसी कर्मकार को किसी विशिष्ट संघ के सदस्य के रूप में माना जाएगा, कि, —

(क) वह किसी भी दिए गए समय पर किसी विशिष्ट संघ के पक्ष में केवल एक चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र दे सकता है; और

(ख) बैंक केवल सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के लिए चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित कर्मकार की सदस्यता प्राप्ति को गणना में लेगा।

3. पदाभिहित अधिकारी, संघ के सदस्यों के नामों को दर्शित करने वाली प्रतिनिधि संघ सूची के संबंध में केंद्रीय सरकार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, संघ, परिसंघ या संगम को उपाबंध-2 के अनुसार सदस्यता के सत्यापन की एक प्रति अग्रेषित करेगा और उनसे यह मांग करेगा कि वे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करें या उनके प्रति कोई आक्षेप, यदि कोई हो, करें।

4. यदि पदाभिहित अधिकारी को सदस्यता के सत्यापन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संघ, परिसंघ या संगम का कोई आक्षेप नहीं है और पदाभिहित अधिकारी तदनुसार आगे कार्यवाही करेगा।

5. संघ, परिसंघ या संगम कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं करेंगे और यदि आक्षेप साधारण या अस्पष्ट है तो ऐसे आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ, परिसंघ या संगम विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे कर्मकार के, जिसके संबंध में आक्षेप किया/किए जा रहे हैं, नाम (नामों), पदनाम (पदनामों), कार्यकरण के स्थान का विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेंगे और आक्षेप के कारणों का भी कथन करेंगे।

6. यदि संघ, परिसंघ या संगम से कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो पदाभिहित अधिकारी उसका इस संबंध में सत्यापन करेगा कि क्या संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, बैंक में कर्मकारों की बहुसंख्या को उसके सदस्यों के रूप में रखने वाले संघ की प्राप्ति जिसे बैंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, परिवर्तित हो जाएगी।

7. यदि संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, प्रतिनिधि संघ के रूप में प्रमाणित संघ की प्राप्ति में परिवर्तन होता है तब पदाभिहित अधिकारी बैंक के प्रधान कार्यालय, निगम कार्यालय, जोनल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय पर चंदा कटौती की प्रणाली के अधीन संघ सदस्यता फीस की कटौती के संबंध में सुसंगत अभिलेखों का सत्यापन करेगा।

8. पदाभिहित अधिकारी, सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए बैंक के सत्यापन अधिकारी (अधिकारियों) को नियुक्त कर सकेगा, जो सत्यापन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ प्रबंधक या मुख्य प्रबंधक की रैंक के समतुल्य होंगे। सत्यापन अधिकारी बैंक और संबंधित संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले संघ द्वारा आक्षेप किए गए नाम का सत्यापन करेगा (करेंगे)। सत्यापन अधिकारी संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों से उसके या उनके किसी एक या किसी अन्य संघ से संबंध के बारे में पूछताछ कर सकेगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ऐसी व्यक्तिगत पूछताछ के

अनुक्रम में, संघ, परिसंघ, संगम या बैंक के प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि उपास्थित नहीं होगा। सत्यापन के पूरा होने के पश्चात्, सत्यापन अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।

9. पैरा 8 के अधीन रहते हुए पदाभिहित अधिकारी संघ की सदस्यता के सत्यापन को अंतिम रूप देगा और सत्यापन को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या, उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बैंक के प्रतिनिधि संघ और निर्वाचन लड़ने वाले संघ, परिसंघ या संगम को भी भेजी जाएगी।

10. यदि विवादास्पद या आक्षेप की गई सदस्यता में अंतर बैंक के कुल कर्मकार कर्मचारिवृंद की संख्या के 5% से अधिक है या प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति को परिवर्तित करने वाला है तो पदाभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकेगी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई संघ, परिसंघ या संगम, पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट को जारी करने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए अपील फाइल कर सकेगा। अपील प्राधिकरण, या तो जांच का संचालन करके या अभिलेखों का अवलोकन करके तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अनधिक अवधि के भीतर लिखित में एक आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति अपील के दोनों पक्षों को भेजी जाएगी। पदाभिहित अधिकारी ऐसे आदेश के आधार पर सूची को उपांतरित करेगा और अपील प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उसे केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

11. प्रतिनिधि संघ से एक पैनल प्राप्त करना — बैंक, पदाभिहित अधिकारी से प्रतिनिधि संघ से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार को संसूचित करते हुए प्रतिनिधि संघ को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिमानतः के क्रम में पदधारियों के तीन नामों का एक पैनल प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि प्रतिनिधि संघ, ऐसे निदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पदधारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बैंक केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा और केंद्रीय सरकार सूचना की प्राप्ति के पश्चात् बैंक के प्रबंधन को 30 दिन की अवधि के भीतर अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों के पैनल को अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परंतु सबसे बड़े संघ के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार बैंक के कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने की अवधि में 15 दिन की और वृद्धि कर सकेगी।

12. प्रतिनिधि संघ या अगला सबसे बड़ा संघ बैंक के प्रबंधन को तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। बैंक का प्रबंधन, नामों का पैनल प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार को पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं भेजेगा, —

- (i) पूर्ण बायो-डाटा ;
- (ii) पिछले पांच वर्ष की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां ;
- (iii) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है या अनुध्यात नहीं किया जा रहा है ;
- (iv) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि वे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरहित नहीं हैं ;

- (v) बैंक के मुख्य कार्यपालक से सत्यनिष्ठा और नैतिक चरित्र का प्रमाणपत्र ;
- (vi) बैंक के विद्यमान निदेशक बोर्ड की संरचना ;
- (vii) पिछले तीन वर्षों के क्रेडिट, निक्षेप और लाभ या हानि से संबंधित आंकड़ें ;
- (viii) बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक के नामनिर्देशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी मामले के लंबित होने के संबंध में पुष्टिकरण ; और
- (ix) बैंक से यह प्रमाणपत्र कि ऐसा कोई स्थगनादेश नहीं है जो केंद्रीय सरकार को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक को नामनिर्देशित करने से प्रतिषिद्ध करें ।

स्पष्टीकरण — इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, “चंदा कटौती” अभिव्यक्ति से किसी संघ के सदस्यों से संघ संबंधी अभिदायों के स्रोत पर मजदूरियों से संग्रहण करने और इस प्रकार कटौती किए गए धन को बैंक द्वारा संघ को अंतरित करने और साथ ही मजदूरियों में से कटौती करने का प्राधिकार देने का भी, जिसमें चंदा कटौती करने की सहमति उपदर्शित हो सकेगी तथा जिस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे, स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 15/5/2003—आई. आर.-(i)]

के. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल स्कीम को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग (ii), खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 3793(अ) तारीख 16 नवंबर, 1970 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :—

क्रम सं.	का.आ. सं.	तारीख
1.	67(अ)	17.11.71
2.	192(अ)	15.03.72
3.	575(अ)	04.09.72
4.	651(अ)	25.09.72
5.	715(अ)	16.11.72
6.	3467	19.11.73
7.	1992	16.06.75
8.	1088	18.02.76
9.	421(अ)	21.06.76
10.	888(अ)	11.11.80
11.	346(अ)	30.04.83
12.	144(अ)	01.03.84
13.	368(अ)	27.04.85
14.	559(अ)	30.07.85
15.	783(अ)	25.10.85
16.	922(अ)	30.12.85
17.	417(अ)	11.07.86

18.	1234(अ)	31.12.88
19.	809(अ)	01.11.92
20.	289(अ)	03.04.95
21.	907(अ)	10.11.95
22.	507(अ)	05.02.96
23.	58(अ)	20.01.2000
24.	1172(अ)	29.12.2000
25.	197(अ)	02.03.2001
26.	251(अ)	19.02.07
27.	334(अ)	08.03.07
28.	1057(अ)	08.03.07

## उपाबंध 1

..... (बैंक) में कार्यरत कर्मकार संघों की सदस्यता संख्या का प्रमाणपत्र

1. सुसंगत वर्ष ..... की 31वीं मार्च को बैंक में नियोजित कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
2. चंदा कटौती प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
3. सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन से चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक में कर्मकार कर्मचारियों के प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	संघ का नाम और पता	संघ का रजिस्ट्रीकरण सं. और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या संघ प्राथमिक है अथवा परिसंघीय ईकाई है	संबंधन		संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के नाम, उनके डाक पत्तों सहित	चंदा कटौती अधिकार पत्र के अनुसार बैंक में सदस्यों की कुल संख्या
				केंद्रीय संगठन	राज्य/अखिल भारतीय परिसंघ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी बैंक में उपलब्ध तथा उसके द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

तारीख :

पदाभिहित अधिकारी

स्थान :

## उपाबंध 2

रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति के साथ प्रथम सूचना

द्वितीय सूचना

बैंक

(प्रधान कार्यालय)

तारीख ....., 200

सं.

सेवा में,

महासचिव,

**विषय : राष्ट्रीकृत बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता का सत्यापन ।**

प्रिय महोदय,

मैं राष्ट्रीकृत बैंकों में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ (प्रति संलग्न है) और मैं इसके साथ सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के आधार पर संघ के सदस्यों की एक ब्यौरेवार सूची संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें कर्मचारी द्वारा दिए गए चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक सदस्य के नाम, पदनाम, कार्य करने की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया गया है ।

2. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सूची का अवलोकन करें और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर सूची के सही होने के संबंध में अपनी स्वीकृति संप्रेक्षित करें ।

3. यदि आपको सूची में किसी कर्मचारी के उपस्थित होने या अन्यथा के संबंध में कोई आक्षेप है, तो आप अपने विनिर्दिष्ट आक्षेपों का कथन करते हुए आक्षेप कर सकते हैं और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकते हैं । कृपया यह नोट करें कि आप बड़ी हुई सदस्यता जैसे कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं उठाएंगे और आक्षेप में ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए, जिनकी संघ के सदस्य होने की बात सूची में दर्शित नहीं की गई है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के नाम भी दिए जाने चाहिए जिनके संघ के सदस्य होने के प्रति आक्षेप किया गया है और उसके कारण भी दिए जाने चाहिए ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करें ।

भवदीय,

पदाभिहित अधिकारी

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रति अग्रेषित की गई :

- (1) अध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (2) कोषाध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (3) संयुक्त सचिव (बैंककारी प्रशासक) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2008

**S.O. 2695(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ( 5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme. further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of clause 2.— In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the said scheme), in clause 2, -

(i) after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely, -

'(ca) "Appellate Authority" means the Central Government or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour, Government of India, as the case may be;'

(ii) in sub-clause (h), for the words and brackets "Chief Labour Commissioner (Central)", the words "Designated Officer" shall be substituted.

3. Amendment of clause 3.- In clause 3 of the said scheme, in sub-clause (2),-

(a) for item (i), the following item shall be substituted, namely, -

"(i) the director referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 9 of the Act shall be nominated by the Central Government from a panel of not less than three number of employees as furnished by the representative Union to the Bank within a period of 30 days from the receipt of such panel :

Provided that on the request of the representative Union, the Central Government may, at its discretion, increase further period of 15 days to furnish the panel of names of employees to the Bank:



Provided further that in case the representative Union fails to furnish the panel of names of employees and does not send the same within the period as specified above, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information from the Bank, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of employees from the next largest Union :

Provided also that in case at any time, if the Central Government is of opinion that there is likely to be delay in the verification and certification of any Union, Federation, Association of the Bank, as a representative Union and it is necessary in the interests of the Nationalized Bank so to do, it may nominate any employee of the Nationalised Bank, who is a workman, to be a director of that Bank.;

(b) sub-item (ii) shall be omitted.

4. Substitution of new Schedule for the First Schedule.- For the First Schedule of the said scheme, the following Schedule shall be substituted, namely,-

#### **' THE FIRST SCHEDULE**

**[See clause 2(h)]**

**Subject : Procedure for verification of membership of Union operating in the Nationalised Bank.**

1. The management of the Bank shall be advised by the Central Government, one year before the expiry of the tenure of the incumbent workmen directors, to verify the membership strength of the Union belonging to workmen employee of the Bank for the purpose of determination of representative Union. The management of the Bank, the Chairman and Managing Director or Executive Director shall nominate an officer at the level of General Manager as the Designated Officer, who shall make the aforesaid verification. The verification of the membership of the Union, Federation or Association is to be done on the basis of the deduction made from the salary of the workmen, for the month of March of the relevant year based on the check off mandate.

2 The data or detail, as the case may be, as per Annexure 1 shall be accompanied by list(s) showing the name of the members of each Union of workmen of the Bank, his or her designation and branch or office where he or she is working shall be compiled immediately on receipt of the advise of the Central Government as referred to in paragraph 1.

*Explanation .-- For the purposes of this paragraph, a workman of the Bank shall be considered as a member of a particular Union, subject to the condition, that,--*

- (a) he can give only one check off mandate in favour of one particular Union at any given point of time; and
- (b) the Bank shall only reckon the membership status of workmen based on the check off mandate for the salary of month of March of the relevant year.

3. The Designated Officer shall, within a period of 7 days from the date of receipt of communication from the Central Government regarding the representative Union list showing the names of members of the Union, forward a copy of the verification of membership as per Annexure - II to the Union, Federation or Association and call

upon them to accept or object its authenticity, if any, within a period of 30 days from the date of receipt of such communication.

4. If no objection is received within a period of 30 days from the date of receipt of the copy of the verification of membership by the Designated Officer, it shall be presumed that there is no objection from the Union, Federation or Association and the Designated Officer shall proceed further accordingly.

5. The Union, Federation or Association shall not raise general or vague objection, and if the objection is general or vague, such objection shall not be considered. The Union, Federation or Association shall specifically state the name(s), designation(s), place of working of the workman in respect of whom objection is or are being raised and the reasons therefor.

6. If any objection is received from the Union, Federation or Association, the Designated Officer shall verify the same as to whether by reckoning the difference in the membership strength as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union having majority of the workmen in the Bank as its members and certified so by the Bank, shall get altered.

7. If by reckoning the difference in the membership strength, as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union certified to be representative Union changes, then the Designated Officer shall verify the relevant records as to the deduction of Union membership fees under the system of check off at Head Office, Corporate Office, Zonal Office or Regional Office of the Bank.

8. The Designated Officer may, for the purpose of the verification of the membership, appoint Verifying Officer(s) of the Bank, who is equivalent to the rank of Senior Manager or Chief Manager as the Verifying Officer. The Verifying Officer(s) shall verify the name objected by the contesting Union in the presence of the representatives of the Bank and the concerned Union. The Verifying Officer may enquire from the concerned employee(s) about his or their affiliation to one or any other Union. In the course of such personal enquiry by the Verifying Officer, no representative of any of the Union, Federation, Association or management of the Bank shall be present. After completion of the verification, the Verifying Officer(s) shall submit his report to the Designated Officer.

9. Subject to paragraph 8, the Designated Officer shall finalize the verification of membership of the Union and submit his report within a period of 7 days from the date of finalization of the verification to the Central Government through the Chairman and Managing Director or, in his absence through the Executive Director of the Bank. A copy of such report shall be sent to the representative Union and contesting Union, Federation or Association of the Bank.

10. An Appeal shall lie against the report of the Designated Officer before the Appellate Authority, if the difference in membership contested or objected is more than 5% of the total workmen employee strength of the Bank or to change the status of the representative Union. Any Union, Federation or Association having objection to the status of representative Union as determined by the Designated Officer may file an appeal, giving reason in writing, within a period of 7 days from the date of issue of such report by the Designated Officer. The Appellate

Authority shall, within a period of not more than 60 days from the date of filing of the Appeal either by conduct of inquiry or by perusal of records and giving an opportunity of being heard to the parties, pass an order in writing. A copy of such order shall be sent to both the parties to the Appeal. The Designated Officer shall modify the list on the basis of such order, and send the same to the Central Government within a period of 7 days from the date of the receipt of the order of the Appellate Authority.

11. Obtaining a panel from representative Union .-- The Bank shall, within a period of 7 days from the date of receipt of the status report of the representative Union from the Designated Officer, ask the representative Union to furnish a panel of three names of the office bearers in order of preference for appointment of workmen director on the Bank's board under intimation to the Central Government. In case the representative Union fails to furnish the panel of names of the office bearers within a period of 30 days from the date of the receipt of such direction, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of the employees from the next largest Union within a period of 30 days:

Provided that on the request of the largest Union, the Central Government may increase further period of 15 days to furnish the panel of the names of employees of the Bank.

12. The representative Union or the next largest Union shall furnish panel of three names to the management of the Bank and send a copy of the same to the Central Government. The management of the Bank on receipt of the panel of names, shall send the following informations in respect of each of the persons in the panel to the Central Government,-

- (i) complete bio-data;
- (ii) copies of the Confidential reports for the last 5 years;
- (iii) certificate to the effect that no vigilance or disciplinary case is pending or being contemplated;
- (iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being nominated as director on the Bank's board as per the provisions of any law for the time being in force;
- (v) integrity and moral character certificate by the Bank's chief executive;
- (vi) composition of the present Board of Directors of the Bank;
- (vii) the data relating to credit, deposit and profit or loss for the last three years;
- (viii) confirmation regarding pendency of any case in any Court with regard to nomination of Workmen Employee Director on the Board of the Bank; and
- (ix) certificate from the Bank that there is no stay order which may prohibit the Central Government to nominate the Workmen Employee Director on the Board of the Bank.

**Explanation.-** For the purposes of this Schedule, the expression "check off" means a voluntary arrangement of collection of the Union subscriptions from the members of a Union from the wages at source and passing off the money so deducted to the Union by the Bank and also the authorization to deduct from the wages which may indicate the consent to make the check off deduction and shall be signed with date.

[F. No. 15/5/2003-IR-(i)]

K. V. EAPEN, Jt. Secy.

**Foot Note :** The Principal Scheme was published in the Gazette of India Extraordinary, Part (ii) Section 3, sub-section (i), vide, notification No.S.O.3793(E) dated 16<sup>th</sup> November, 1970 and subsequently amended, vide, notifications:-

S.No.	S.O. No.	Date
1.	67(E)	17-11-71
2.	192(E)	15-3-72
3.	575(E)	4-9-72
4.	651(E)	25-9-72
5.	715(E)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(E)	21-6-76
10.	888(E)	11-11-80
11.	346(E)	30-4-83
12.	144(E)	1-3-84
13.	368(E)	27-4-85
14.	559(E)	30-7-85
15.	783(E)	25-10-85
16.	922(E)	30-12-85
17.	417(E)	11-7-86
18.	1234(E)	31-12-88
19.	809(E)	1-11-92
20.	289(E)	3-4-95
21.	907(E)	10-11-95
22.	507(E)	5-2-96
23.	58(E)	20-1-2000
24.	1172(E)	29-12-2000
25.	197(E)	2-3-2001
26.	251(E)	19-2-07
27.	334(E)	8-3-07
28.	1057(E)	8-3-07

## ANNEXURE I

**Certificate of membership strength of workmen unions functioning in.....(Bank)**

1. The total number of workmen employee employed in the Bank as on 31<sup>st</sup> March of the relevant year \_\_\_\_
2. The total number of workmen employee covered by the check off system:
3. The membership strength of each Union of workmen employee in the bank based on check off mandate for the salary for the month of March of the relevant year, is as follows:-

Sl. No.	Name and address of the Union	Registration No. and date of Registration of the Union	Whether the Union is primary or federating unit	Affiliation		Name of the President, General Secretary, Treasurer of the Union with their postal addresses	Total membership in the bank as per check off mandate
				Central Organisation	State/All India Federation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the above information is true and correct as per records available in, and maintained by, the Bank.

Date:-

Designated Officer

Place:-

## ANNEXURE II

First Notice by Regd. A.D.  
Second Notice

BANK  
(Head Office)

dated the....., 200

No.

To,

The General Secretary,

.....

.....

**Subject:- Verification of membership of Union operating in Nationalised Bank.**

Dear Sir,

I am to invite the reference to the procedure for verification of membership of Union operating in the Nationalised Banks (copy enclosed) and I am enclosing herewith a detailed list of membership of Union based on the salary for the month of March of the relevant year, showing the names of each member, designation, branch or office where working, as provided by the bank based on the check off mandates given by the employee.

2. I request you to peruse the list and convey your acceptance thereof as to the correctness of the list, within 30 days from the date of receipt of this Annexure.

3. In case you have any objection to the presence or otherwise of an employee in the list, you may raise objection by stating your specific objections and forward it to the undersigned within a period of 30 days from the date of receipt of this Annexure. Please note that you shall not raise any general or vague objections like inflated membership and the objection should give names of persons whose membership to the Union is not reflected in the list as also the names of persons whose membership in the Union is objected to and the reason therefor.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Designated Officer

Copy forwarded for information to:-

- (1) The President ..... (Name and address of the Union)
- (2) The Treasurer ..... (Name and address of the Union)
- (3) Joint Secretary (Banking Administration), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 2696(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंककासी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. खंड 2 का संशोधन- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), के खंड 2 में,—

(i) उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है ;”;

(ii) उपखंड (ज) में, “मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “पदाभिहित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ।

3. खंड 3 का संशोधन- उक्त स्कीम के खंड 3 के उपखंड (2) में,—

(क) मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आधोनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) में निदिष्ट निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन से अन्यून कर्मचारियों के ऐसे पैनल से, जो प्रतिनिधि संघ द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे पैनल की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रतिनिधि संघ के अनुरोध पर, स्वविवेकानुसार, बैंक के लिए कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने के लिए अवधि को 15 दिन के लिए और बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रतिनिधि संघ कर्मचारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करने में असफल रहता है और ऊपर यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसको नहीं भेजता है तो बैंक केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और बैंक से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, बैंक के प्रबंधन से अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों का पैनल अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी प्रतिनिधि संघ के रूप में बैंक के किसी संघ, परिसंघ, संगम के सत्यापन या प्रमाणीकरण में विलंब होने की संभावना है और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी कर्मचारी को जो कोई कर्मकार है उस बैंक के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।”;

(ख) उपमद (ii) का लोप किया जाएगा ।

4. प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन किया जाना- उक्त स्कीम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

**‘पहली अनुसूची**  
**[खंड 2(ज) देखिए]**

**विषय : राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया ।**

1. पदधारी कर्मकार निदेशकों के कार्यकाल के अवसान से एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार बैंक के प्रबंधन को, प्रतिनिधि संघ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बैंक के कर्मकार कर्मचारी से संबंधित संघ की सदस्यता की पदसंख्या का सत्यापन करने की सलाह देगी । बैंक का प्रबंधन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक के स्तर के किसी अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो पूर्वोक्त सत्यापन करेगा । संघ, परिसंघ या संगम की सदस्यता का सत्यापन चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित सुसंगत वर्ष के मार्च मास के लिए कर्मकार के वेतन से की गई कटौती के आधार पर किया जाना है ।

2. उपाबंध 1 के अनुसार, यथास्थिति, आंकड़ों या ब्यौरों के साथ सूची (सूचियाँ) संलग्न होगी, जिनमें बैंक के कर्मकारों के प्रत्येक संघ के सदस्यों के नाम, उसका पदनाम और उसके कार्यकरण की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया जाएगा, ऐसी सूची (सूचियों) को पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की सलाह की प्राप्ति पर तुरंत संकलित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** — इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए, बैंक के किसी कर्मकार को किसी विशिष्ट संघ के सदस्य के रूप में माना जाएगा, कि, —

(क) वह किसी भी दिए गए समय पर किसी विशिष्ट संघ के पक्ष में केवल एक चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र दे सकता है ; और

(ख) बैंक केवल सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के लिए चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित कर्मकार की सदस्यता प्रास्थिति को गणना में लेगा ।

3. पदाभिहित अधिकारी, संघ के सदस्यों के नामों को दर्शित करने वाली प्रतिनिधि संघ सूची के संबंध में केन्द्रीय सरकार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, संघ, परिसंघ या संगम को उपाबंध-2 के अनुसार सदस्यता के सत्यापन की एक प्रति अग्रेषित करेगा और उनसे यह मांग करेगा कि वे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करें या उनके प्रति कोई आक्षेप, यदि कोई हों, करें ।

4. यदि पदाभिहित अधिकारी को सदस्यता के सत्यापन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संघ, परिसंघ या संगम का कोई आक्षेप नहीं है और पदाभिहित अधिकारी तदनुसार आगे कार्यवाही करेगा ।



5. संघ, परिसंघ या संगम कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं करेंगे और यदि आक्षेप साधारण या अस्पष्ट है तो ऐसे आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ, परिसंघ या संगम विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे कर्मकार के, जिसके संबंध में आक्षेप किया/किए जा रहे हैं, नाम (नामों), पदनाम (पदनामों), कार्यकरण के स्थान का विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेंगे और आक्षेप के कारणों का भी कथन करेंगे।
6. यदि संघ, परिसंघ या संगम से कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो पदाभिहित अधिकारी उसका इस संबंध में सत्यापन करेगा कि क्या संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, बैंक में कर्मकारों की बहुसंख्या को उसके सदस्यों के रूप में रखने वाले संघ की प्रास्थिति जिसे बैंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, परिवर्तित हो जाएगी।
7. यदि संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, प्रतिनिधि संघ के रूप में प्रमाणित संघ की प्रास्थिति में परिवर्तन होता है तब पदाभिहित अधिकारी बैंक के प्रधान कार्यालय, निगम कार्यालय, जूनल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय पर चंदा कटौती की प्रणाली के अधीन संघ सदस्यता फीस की कटौती के संबंध में सुसंगत अभिलेखों का सत्यापन करेगा।
8. पदाभिहित अधिकारी, सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए बैंक के सत्यापन अधिकारी (अधिकारियों) को नियुक्त कर सकेगा, जो सत्यापन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ प्रबंधक या मुख्य प्रबंधक की रैंक के समतुल्य होंगे। सत्यापन अधिकारी बैंक और संबंधित संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले संघ द्वारा आक्षेप किए गए नाम का सत्यापन करेगा (करेंगे)। सत्यापन अधिकारी संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों से उसके या उनके किसी एक या किसी अन्य संघ से संबंध के बारे में पूछताछ कर सकेगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ऐसी व्यक्तिगत पूछताछ के अनुक्रम में, संघ, परिसंघ, संगम या बैंक के प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा। सत्यापन के पूरा होने के पश्चात्, सत्यापन अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।
9. पैरा 8 के अधीन रहते हुए पदाभिहित अधिकारी संघ की सदस्यता के सत्यापन को अंतिम रूप देगा और सत्यापन को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या, उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बैंक के प्रतिनिधि संघ और निर्वाचन लड़ने वाले संघ, परिसंघ या संगम को भी भेजी जाएगी।
10. यदि विवादस्पद या आक्षेप की गई सदस्यता में अंतर बैंक के कुल कर्मकार कर्मचारिवृंद की संख्या के 5% से अधिक है या प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति को परिवर्तित करने वाला है तो पदाभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकेगी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई संघ, परिसंघ या संगम, पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट को जारी करने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए अपील फाइल कर सकेगा। अपील प्राधिकरण, या तो जांच का संचालन करके या अभिलेखों का अवलोकन करके तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अनधिक अवधि के भीतर लिखित में एक आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति अपील के दोनों पक्षों को भेजी जाएगी। पदाभिहित अधिकारी ऐसे आदेश के आधार पर सूची को उपांतरित करेगा और अपील प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उसे केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

11. प्रतिनिधि संघ से एक पैनल प्राप्त करना — बैंक, पदाभिहित अधिकारी से प्रतिनिधि संघ से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार को संसूचित करते हुए प्रतिनिधि संघ को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिमानतः के क्रम में पदधारियों के तीन नामों का एक पैनल प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि प्रतिनिधि संघ, ऐसे निदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पदधारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बैंक केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा और केंद्रीय सरकार सूचना की प्राप्ति के पश्चात् बैंक के प्रबंधन को 30 दिन की अवधि के भीतर अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों के पैनल को अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परंतु सबसे बड़े संघ के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार बैंक के कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने की अवधि में 15 दिन की और वृद्धि कर सकेगी।

12. प्रतिनिधि संघ या अगला सबसे बड़ा संघ बैंक के प्रबंधन को तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। बैंक का प्रबंधन, नामों का पैनल प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार को पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं भेजेगा, —

- (i) पूर्ण बायो-डाटा ;
- (ii) पिछले पांच वर्ष की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां ;
- (iii) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है या अनुध्यात नहीं किया जा रहा है ;
- (iv) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि वे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरर्हित नहीं हैं ;
- (v) बैंक के मुख्य कार्यपालक से सत्यनिष्ठा और नैतिक चरित्र का प्रमाणपत्र ;
- (vi) बैंक के विद्यमान निदेशक बोर्ड की संरचना ;
- (vii) पिछले तीन वर्षों के क्रेडिट, निक्षेप और लाभ या हानि से संबंधित आंकड़ें ;
- (viii) बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक के नामनिर्देशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी मामले के लंबित होने के संबंध में पुष्टिकरण ; और
- (ix) बैंक से यह प्रमाणपत्र कि ऐसा कोई स्थगनादेश नहीं है जो केंद्रीय सरकार को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक को नामनिर्देशित करने से प्रतिषिद्ध करें।

स्पष्टीकरण — इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, “चंदा कटौती” अभिव्यक्ति से किसी संघ के सदस्यों से संघ संबंधी अभिदायों के स्रोत पर मजदूरियों से संग्रहण करने और इस प्रकार कटौती किए गए धन को बैंक द्वारा संघ को अंतरित करने और साथ ही मजदूरियों में से कटौती करने का प्राधिकार देने का भी, जिसमें चंदा कटौती करने की सहमति उपदर्शित हो सकेगी तथा जिस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे, स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है।

[फा. सं. 15/5/2003-आई. आर.-(ii)]

के. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल स्कीम को अधिसूचना सं. का.आ. 875(अ) तारीख 4 नवंबर, 1980 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :-

क्रम सं.	का.आ. सं.	तारीख
1.	345(अ)	30.4.83
2.	145(अ)	1.08.84
3.	369(अ)	27.4.85
4.	560(अ)	30.7.85
5.	784(अ)	25.10.85
6.	923(अ)	30.12.85
7.	418(अ)	11.7.86
8.	123(अ)	30.12.88
9.	810(अ)	1.11.92
10.	290(अ)	3.4.95
11.	908(अ)	10.11.95
12.	508(अ)	5.2.96
13.	59(अ)	20.1.2000
14.	1173(अ)	29.12.2000
15.	198(अ)	2.3.2001
16.	252(अ)	19.2.07
17.	335(अ)	8.3.07
18.	1058(अ)	29.6.2007

## उपाबंध 1

..... (बैंक) में कार्यरत कर्मकार संघों की सदस्यता संख्या का प्रमाणपत्र

1. सुसंगत वर्ष ..... की 31वीं मार्च को बैंक में नियोजित कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
2. चंदा कटौती प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
3. सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन से चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक में कर्मकार कर्मचारियों के प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	संघ का नाम और पता	संघ का रजिस्ट्रीकरण सं. और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या संघ प्राथमिक है अथवा परिसंघीय ईकाई है	संबंधन		संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के नाम, उनके डाक पत्तों सहित	चंदा कटौती अधिकार पत्र के अनुसार बैंक में सदस्यों की कुल संख्या
				केंद्रीय संगठन	राज्य/अखिल भारतीय परिसंघ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी बैंक में उपलब्ध तथा उसके द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

तारीख :

पदाभिहित अधिकारी

स्थान :

## उपाबंध 2

रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति के साथ प्रथम सूचना

द्वितीय सूचना

बैंक

(प्रधान कार्यालय)

तारीख ....., 200

सं.

सेवा में,

महासचिव,

.....

.....

**विषय : राष्ट्रीकृत बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता का सत्यापन ।**

प्रिय महोदय,

मैं राष्ट्रीकृत बैंकों में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ (प्रति संलग्न है) और मैं इसके साथ सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के आधार पर संघ के सदस्यों की एक ब्यौरेवार सूची संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें कर्मचारी द्वारा दिए गए चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक सदस्य के नाम, पदनाम, कार्य करने की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया गया है ।

2. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सूची का अवलोकन करें और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर सूची के सही होने के संबंध में अपनी स्वीकृति संप्रेक्षित करें ।

3. यदि आपको सूची में किसी कर्मचारी के उपस्थित होने या अन्यथा के संबंध में कोई आक्षेप है, तो आप अपने विनिर्दिष्ट आक्षेपों का कथन करते हुए आक्षेप कर सकते हैं और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकते हैं । कृपया यह नोट करें कि आप बढी हुई सदस्यता जैसे कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं उठाएंगे और आक्षेप में ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए, जिनकी संघ के सदस्य होने की बात सूची में दर्शित नहीं की गई है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के नाम भी दिए जाने चाहिए जिनके संघ के सदस्य होने के प्रति आक्षेप किया गया है और उसके कारण भी दिए जाने चाहिए ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करें ।

भवदीय,

पदाभिहित अधिकारी

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रति अग्रेषित की गई :

- (1) अध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (2) कोषाध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (3) संयुक्त सचिव (बैंककारी प्रशासक), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

**S.O. 2696(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of clause 2.- In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, (hereinafter referred to as the said scheme), in clause 2, -

(i) after sub-clause (c), the following sub-clause shall be inserted, namely, -

'(ca) "Appellate Authority" means the Central Government or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour, Government of India, as the case may be.';

(ii) in sub-clause (h), for the words and bracket "Chief Labour Commissioner (Central)", the words "Designated Officer" shall be substituted.

3. Amendment of clause 3.- In clause 3 of the said scheme, in sub-clause (2),-

(a) for item (i), the following item shall be substituted, namely, -

"(i) the director referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 9 of the Act shall be nominated by the Central Government from a panel of not less than three number of employees as furnished by the representative Union to the Bank within a period of 30 days from the receipt of such panel:

Provided that on the request of the representative union, the Central Government may, at its discretion, increase further period of 15 days to furnish the panel of names of employees to the Bank:

Provided further that in case the representative Union fails to furnish the panel of names of employees and does not send the same within the period as specified above, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information from the Bank, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of employees from the next largest Union:

Provided also that in case at any time, if the Central Government is of opinion that there is likely to be delay in the verification and certification of any Union, Federation, Association of the Bank, as a representative Union and it is necessary in the interests of the Nationalized Bank so to do, it may nominate any employee of the Nationalised Bank who is a workman, to be a director of that Bank.;

(b) sub-item (ii) shall be omitted.

4. Substitution of new Schedule for the First Schedule.- For the First Schedule of the said scheme, the following Schedule shall be substituted, namely,-

#### **THE FIRST SCHEDULE**

[See clause 2(h)]

**Subject :** Procedure for verification of membership of Union operating in the Nationalised Bank.

1. The management of the Bank shall be advised by the Central Government, one year before the expiry of the tenure of the incumbent workmen directors, to verify the membership strength of the Union belonging to workman employees of the Bank for the purpose of determination of representative Union. The management of the Bank, the Chairman and Managing Director or Executive Director shall nominate an officer at the level of General Manager as the Designated Officer, who shall make the aforesaid verification. The verification of the membership of the Union, Federation or Association is to be done on the basis of the deduction made from the salary of the workmen for the month of March of the relevant year based on the check off mandate.

2. The data or detail, as the case may be, as per Annexure 1 shall be accompanied by list(s) showing the name of the members of each Union of workmen of the Bank, his or her designation and branch or office where he or she is working shall be compiled immediately on receipt of the advise of the Central Government as referred to in paragraph 1.

*Explanation.-- For the purposes of this paragraph, a workman of the Bank shall be considered as a member of a particular Union, subject to the condition, that, -*

(a) he can give only one check off mandate in favour of one particular Union at any given point of time; and

(b) *the Bank shall only reckon the membership status of workmen based on the check off mandate for the salary of month of March of the relevant year.*

3. The Designated Officer shall, within a period of 7 days from the date of receipt of communication from the Central Government regarding the representative Union list showing the names of members of the Union, forward a copy of the verification of membership as per Annexure – II to the Union, Federation or Association and call upon them to accept or object its authenticity, if any, within a period of 30 days from the date of receipt of such communication.
4. If no objection is received within a period of 30 days from the date of receipt of the copy of the verification of membership by the Designated Officer, it shall be presumed that there is no objection from the Union, Federation or Association and the Designated Officer shall proceed further accordingly.
5. The Union, Federation or Association shall not raise general or vague objection, and if the objection is general or vague, such objection shall not be considered. The Union, Federation or Association shall specifically state the name(s), designation(s), place of working of the workman in respect of whom objection is or are being raised and the reasons therefor.
6. If any objection is received from the Union, Federation or Association, the Designated Officer shall verify the same as to whether by reckoning the difference in the membership strength as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union having majority of the workmen in the Bank as its members and certified so by the Bank, shall get altered.
7. If by reckoning the difference in the membership strength, as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union certified to be representative Union changes, then the Designated Officer shall verify the relevant records as to the deduction of Union membership fees under the system of check off at Head Office, Corporate Office, Zonal Office or Regional Office of the Bank.
8. The Designated Officer may, for the purpose of the verification of the membership, appoint Verifying Officer(s) of the Bank, who is equivalent to the rank of Senior Manager or Chief Manager as the Verifying Officer. The Verifying Officer(s) shall verify the name objected by the contesting Union in the presence of the representatives of the Bank and the concerned Union. The Verifying Officer may enquire from the concerned employee(s) about his or their affiliation to one or any other Union. In the course of such personal enquiry by the Verifying Officer(s), no representative of any of the Union, Federation, Association or management of the Bank shall be present. After completion of the verification, the Verifying Officer(s) shall submit his report to the Designated Officer.



9. Subject to paragraph 8, the Designated Officer shall finalize the verification of membership of the Union and submit his report within a period of 7 days from the date of finalization of the verification to the Central Government through the Chairman and Managing Director or, in his absence through the Executive Director of the Bank. A copy of such report shall be sent to the representative Union and contesting Union, Federation or Association of the Bank.

10. An Appeal shall lie against the report of the Designated Officer before the Appellate Authority if the difference in membership contested or objected is more than 5% of the total workmen employee strength of the Bank or to change the status of the representative Union. Any Union, Federation or Association having objection to the status of representative Union as determined by the Designated Officer may file an appeal, giving reason in writing, within a period of 7 days from the date of issue of such report by the Designated Officer. The Appellate Authority shall, within a period of not more than 60 days from the date of filing of the Appeal either by conduct of inquiry or by perusal of records and giving an opportunity of being heard to the parties, pass an order in writing. A copy of such order shall be sent to both the parties to the Appeal. The Designated Officer shall modify the list on the basis of such order, and send the same to the Central Government within a period of 7 days from the date of the receipt of the order of the Appellate Authority.

11. Obtaining a panel from representative Union .-- The Bank shall, within a period of 7 days from the date of receipt of the status report of the representative Union from the Designated Officer, ask the representative Union to furnish a panel of three names of the office bearers in order of preference for appointment of workmen director on the Bank's board under intimation to the Central Government. In case the representative Union fails to furnish the panel of names of the office bearers within a period of 30 days from the date of the receipt of such direction, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of the employees from the next largest Union within a period of 30 days:

Provided that on the request of the largest Union, the Central Government may increase further period of 15 days to furnish the panel of the names of employees of the Bank.

12. The representative Union or the next largest Union shall furnish panel of three names to the management of the Bank and send a copy of the same to the Central Government. The management of the Bank on receipt of the panel of names, shall send the following informations in respect of each of the persons in the panel to the Central Government,-

- (i) complete bio-data;
- (ii) copies of the Confidential reports for the last 5 years;

- (iii) certificate to the effect that no vigilance or disciplinary case is pending or being contemplated;
- (iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being nominated as director on the Bank's board as per the provisions of any law for the time being in force;
- (v) integrity and moral character certificate by the Bank's chief executive;
- (vi) composition of the present Board of Directors of the Bank;
- (vii) the data relating to credit, deposit and profit or loss for the last three years;
- (viii) confirmation regarding pendency of any case in any Court with regard to nomination of Workmen Employee Director on the Board of the Bank; and
- (ix) certificate from the Bank that there is no stay order which may prohibit the Central Government to nominate the Workmen Employee Director on the Board of the Bank.

Explanation.- For the purposes of this Schedule, the expression "check off" means a voluntary arrangement of collection of the Union subscriptions from the members of a Union from the wages at source and passing off the money so deducted to the Union by the Bank and also the authorization to deduct from the wages which may indicate the consent to make the check off deduction and shall be signed with date.

[F. No. 15/5/2003-IR-(ii)]

K. V. EAPEN, Jt. Secy.

**Foot Note :** The Principal Scheme was published, vide, notification No.S.O.875(E), dated 4<sup>th</sup> November, 1980 and subsequently amended, vide, notifications:-

S.No.	S.O. No.	Date
1.	345(E)	30-4-83
2.	145(E)	1-3-84
3.	369(E)	27-4-85
4.	560(E)	30-7-85
5.	784(E)	25-10-85
6.	923(E)	30-12-85
7.	418(E)	11-7-86
8.	123(F)	30-12-88
9.	810(F)	1-11-92
10.	290(F)	3-4-95
11.	908(F)	10-11-95
12.	508(E)	5-2-96
13.	59(E)	20-1-2000
14.	1173(E)	29-12-2000
15.	198(E)	2-3-2001
16.	252(E)	19-2-07
17.	335(E)	8-3-07
18.	1058(E)	29-6-2007

## ANNEXURE I

**Certificate of membership strength of workmen unions functioning in.....(Bank)**

1. The total number of workmen employee employed in the Bank as on 31<sup>st</sup> March of the relevant year \_\_\_\_
2. The total number of workmen employee covered by the check off system: \_\_\_\_
3. The membership strength of each Union of workmen employee in the bank based on check off mandate for the salary for the month of March of the relevant year, is as follows,-

Sl. No.	Name and address of the Union	Registration No. and date of Registration of the Union	Whether the Union is primary or federating unit	Affiliation		Name of the President, General Secretary, Treasurer of the Union with their postal addresses	Total membership in the bank as per check off mandate
				Central Organisation	State/All India Federation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the above information is true and correct as per records available in, and maintained by, the Bank.

Date:-

Designated Officer

Place:-

## ANNEXURE II

First Notice by Regd. A.D.  
Second Notice

BANK  
(Head Office)

dated the....., 200

No.

To,

The General Secretary,

.....

.....

**Subject:- Verification of membership of Union operating in Nationalised Bank.**

Dear Sir,

I am to invite the reference to the procedure for verification of membership of Union operating in the Nationalised Banks (copy enclosed) and I am enclosing herewith a detailed list of membership of Union based on the salary for the month of March of the relevant year, showing the names of each member, designation, branch or office where working, as provided by the bank based on the check off mandates given by the employee.

2. I request you to peruse the list and convey your acceptance thereof as to the correctness of the list, within 30 days from the date of receipt of this Annexure.

3. In case you have any objection to the presence or otherwise of an employee in the list, you may raise objection by stating your specific objections and forward it to the undersigned within a period of 30 days from the date of receipt of this Annexure. Please note that you shall not raise any general or vague objections like inflated membership and the objection should give names of persons whose membership to the Union is not reflected in the list as also the names of persons whose membership in the Union is objected to and the reason therefor.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Designated Officer

Copy forwarded for information to:-

- (1) The President ..... (Name and address of the Union)
- (2) The Treasurer ..... (Name and address of the Union)
- (3) Joint Secretary (Banking Administration), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 2697(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन- भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है ;”;

(ii) खंड (ग) में, “मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “पदाभिहित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ।

3. नियम 3 का संशोधन- उक्त नियम के नियम 3 में, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. कर्मकार कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति— अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन से अधिक कर्मचारियों के ऐसे पैनल से, जो प्रतिनिधि संघ द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे पैनल की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रतिनिधि संघ के अनुरोध पर सह-निदेशकसमूह बैंक के लिए कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने के लिए अवधि को 15 दिनों के लिए और बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रतिनिधि संघ कर्मचारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करने में असफल रहता है और ऊपर यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसको नहीं भेजता है तो बैंक केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और बैंक से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, बैंक के प्रबंधन से अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों का पैनल अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार को यह लगे कि किसी प्रतिनिधि संघ के रूप में बैंक के किसी संघ, परिसंघ, संगठन के स्थापन या प्रयोग में विलंब होने की संभावना है और किसी स्टेट बैंक के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी को जो कोई कर्मकार है उस बैंक के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।”।

4. प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन किया जाना— उक्त नियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘पहली अनुसूची  
[खंड 2(ग) देखिए]

**विषय : स्टेट बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सफलता के स्थापन के लिए प्रक्रिया ।**

1. पदचारी कर्मकार निदेशकों के कार्यकाल के अन्तर्गत से एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार बैंक के प्रबंधन को, प्रतिनिधि संघ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बैंक के कर्मकार कर्मचारी से संबंधित संघ की सदस्यता की पदसंख्या का स्थापन करने की सलाह देगी । बैंक का प्रबंधन या अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक के स्तर के किसी अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो पूर्वोक्त स्थापन करेगा । संघ, परिसंघ या संगठन की सदस्यता का स्थापन चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित सुसंगत वर्ष के माते मास के लिए कर्मकार के वेतन से की गई कटौती के आधार पर किया जाना है ।

2. उपाबंध 1 के अनुसार, यथास्थिति, आंकड़ों या ब्यौरों के साथ सूची (सूचियाँ) संलग्न होगी, जिनमें बैंक के कर्मकारों के प्रत्येक संघ के सदस्यों के नाम, उसका पदनाम और उसके कार्यकरण की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया जाएगा, ऐसी सूची (सूचियाँ) को पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार की सलाह की प्राप्ति पर तुरंत संकलित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण** — इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए, बैंक के किसी कर्मकार को किसी विशिष्ट संघ के सदस्य के रूप में माना जाएगा, कि, —

(क) वह किसी भी दिए गए समय पर किसी विशिष्ट संघ के पक्ष में केवल एक चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र दे सकता है ; और

(ख) बैंक केवल सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के लिए चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित कर्मकार की सदस्यता प्रास्थिति को गणना में लेगा।

3. पदाभिहित अधिकारी, संघ के सदस्यों के नामों को दर्शित करने वाली प्रतिनिधि संघ सूची के संबंध में केंद्रीय सरकार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, संघ, परिसंघ या संगम को उपाबंध-2 के अनुसार सदस्यता के सत्यापन की एक प्रति अग्रेषित करेगा और उनसे यह मांग करेगा कि वे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करें या उनके प्रति कोई आक्षेप, यदि कोई हों, करें।

4. यदि पदाभिहित अधिकारी को सदस्यता के सत्यापन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संघ, परिसंघ या संगम का कोई आक्षेप नहीं है और पदाभिहित अधिकारी तदनुसार आगे कार्यवाही करेगा।

5. संघ, परिसंघ या संगम कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं करेंगे और यदि आक्षेप साधारण या अस्पष्ट है तो ऐसे आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ, परिसंघ या संगम विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे कर्मकार के, जिसके संबंध में आक्षेप किया/किए जा रहे हैं, नाम (नामों), पदनाम (पदनामों), कार्यकरण के स्थान का विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेंगे और आक्षेप के कारणों का भी कथन करेंगे।

6. यदि संघ, परिसंघ या संगम से कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो पदाभिहित अधिकारी उसका इस संबंध में सत्यापन करेगा कि क्या संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, बैंक में कर्मकारों की बहुसंख्या को उसके सदस्यों के रूप में रखने वाले संघ की प्रास्थिति जिसे बैंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, परिवर्तित हो जाएगी।

7. यदि संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, प्रतिनिधि संघ के रूप में प्रमाणित संघ की प्रास्थिति में परिवर्तन होता है तब पदाभिहित अधिकारी बैंक के प्रधान कार्यालय, निगम कार्यालय, जोनल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय पर चंदा कटौती की प्रणाली के अधीन संघ सदस्यता फीस की कटौती के संबंध में सुसंगत अभिलेखों का सत्यापन करेगा।

8. पदाभिहित अधिकारी, सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए बैंक के सत्यापन अधिकारी (अधिकारियों) को नियुक्त कर सकेगा, जो सत्यापन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ प्रबंधक या मुख्य

प्रबंधक की रैंक के समतुल्य होंगे। सत्यापन अधिकारी बैंक और संबंधित संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले संघ द्वारा आक्षेप किए गए नाम का सत्यापन करेगा (करेंगे)। सत्यापन अधिकारी संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों से बातचीत या उनसे किसी एक या किसी अन्य संघ से संबंध के बारे में पूछताछ कर सकेगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ऐसी व्यक्तिगत पूछताछ के अनुक्रम में, संघ, परिसंघ, संगम या बैंक के प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा। सत्यापन के पूरा होने के पश्चात्, सत्यापन अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।

9. पैरा 8 के अधीन रहते हुए पदाभिहित अधिकारी संघ की सदस्यता के सत्यापन को अंतिम रूप देगा और सत्यापन को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या, उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यवाहक निदेशक के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बैंक के प्रतिनिधि संघ और निर्वाचन लड़ने वाले संघ, परिसंघ या संगम को भी भेजी जाएगी।

10. यदि विवादास्पद या आक्षेप की गई समस्या में अंतर बैंक के कुल कर्मकार कर्मचारिवृंद की संख्या के 5% से अधिक है या प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति को परिवर्तित करने वाला है तो पदाभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई संघ, परिसंघ या संगम, पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट को जारी करने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए अपील फाइल कर सकेगा। अपील प्राधिकरण, या तो जांच का संचालन करके या अभिलेखों का समीक्षण करके तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अधिक अवधि के भीतर लिखित में एक आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति अपील के दोनों पक्षों को भेजी जाएगी। पदाभिहित अधिकारी ऐसे आदेश के आधार पर सूची को उपस्थित करेगा और अपील प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उसे केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

11. प्रतिनिधि संघ से एक पैनल प्राप्त करना -- बैंक, पदाभिहित अधिकारी से प्रतिनिधि संघ से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार को संसूचित करते हुए प्रतिनिधि संघ को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिमानतः के क्रम में पदधारियों के तीन नामों का एक पैनल प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि प्रतिनिधि संघ, ऐसे निदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पदधारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बैंक केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा और केंद्रीय सरकार सूचना की प्राप्ति के पश्चात् बैंक के प्रबंधन को 30 दिन की अवधि के भीतर अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों के पैनल को अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी।

परंतु सबसे बड़े संघ के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार बैंक के कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने की अवधि में 15 दिन की और वृद्धि कर सकेगी।

12. प्रतिनिधि संघ या अगला सबसे बड़ा संघ बैंक के प्रबंधन को तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। बैंक का प्रबंधन, नामों का पैनल प्राप्त होने



पर, केंद्रीय सरकार को पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं भेजेगा, —

- (i) पूर्ण बायो-डाटा ;
- (ii) पिछले पांच वर्ष की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां ;
- (iii) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है या अनुध्यात नहीं किया जा रहा है ;
- (iv) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि वे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरर्हित नहीं हैं ;
- (v) बैंक के मुख्य कार्यपालक से सत्यनिष्ठा और नैतिक चरित्र का प्रमाणपत्र ;
- (vi) बैंक के विद्यमान निदेशक बोर्ड की संरचना ;
- (vii) पिछले तीन वर्षों के क्रेडिट, निक्षेप और लाभ या हानि से संबंधित आंकड़ें ;
- (viii) बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक के नामनिर्देशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी मामले के लंबित होने के संबंध में पुष्टिकरण ; और
- (ix) बैंक से यह प्रमाणपत्र कि ऐसा कोई स्थगनादेश नहीं है जो केंद्रीय सरकार को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक को नामनिर्देशित करने से प्रतिषिद्ध करें ।

स्पष्टीकरण — इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, “चंदा कटौती” अभिव्यक्ति से किसी संघ के सदस्यों से संघ संबंधी अभिदायों के स्रोत पर मजदूरियों से संग्रहण करने और इस प्रकार कटौती किए गए धन को बैंक द्वारा संघ को अंतरित करने और साथ ही मजदूरियों में से कटौती करने का प्राधिकार देने का भी, जिसमें चंदा कटौती करने की सहमति उपदर्शित हो सकेगी तथा जिस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे, स्वेच्छिक कथार अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 15/5/2003-आई. आर.-(iii)]

के. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग (ii), खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) तारीख 29 जून, 1974 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 1976 में संशोधित किया गया था ।

## उपाबंध 1

..... (बैंक) में कार्यरत कर्मकार संघों की सदस्यता संख्या का प्रमाणपत्र

1. सुसंगत वर्ष ..... की 31वीं मार्च को बैंक में नियोजित कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
2. चंदा कटौती प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
3. सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन से चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक में कर्मकार कर्मचारियों के प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	संघ का नाम और पता	संघ का रजिस्ट्रीकरण सं. और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या संघ प्राथमिक है अथवा परिसंघीय ईकाई है	संबंधन		संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के नाम, उनके डाक पत्तों सहित	चंदा कटौती अधिकार पत्र के अनुसार बैंक में सदस्यों की कुल संख्या
				केंद्रीय संगठन	राज्य/अखिल भारतीय परिसंघ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी बैंक में उपलब्ध तथा उसके द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

तारीख :

पदाभिहित अधिकारी

स्थान :

## उपाबंध 2

रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति के साथ प्रथम सूचना

द्वितीय सूचना

बैंक

(प्रधान कार्यालय)

तारीख ....., 200

सं.

सेवा में,

महासचिव,

.....  
.....**विषय : भारतीय स्टेट बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता का सत्यापन ।**

प्रिय महोदय,

मैं भारतीय स्टेट बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ (प्रति संलग्न है) और मैं इसके साथ सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के आधार पर संघ के सदस्यों की एक ब्यौरेवार सूची संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें कर्मचारी द्वारा दिए गए चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक सदस्य के नाम, पदनाम, कार्य करने की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया गया है ।

2. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सूची का अवलोकन करें और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर सूची के सही होने के संबंध में अपनी स्वीकृति संप्रेक्षित करें ।

3. यदि आपको सूची में किसी कर्मचारी के उपस्थित होने या अन्यथा के संबंध में कोई आक्षेप है, तो आप अपने विनिर्दिष्ट आक्षेपों का कथन करते हुए आक्षेप कर सकते हैं और इस उपाबंध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकते हैं । कृपया यह नोट करें कि आप बड़ी हुई सदस्यता जैसे कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं उठाएंगे और आक्षेप में ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए, जिनकी संघ के सदस्य होने की बात सूची में दर्शित नहीं की गई है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के नाम भी दिए जाने चाहिए जिनके संघ के सदस्य होने के प्रति आक्षेप किया गया है और उसके कारण भी दिए जाने चाहिए ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करें ।

महोदय,

पदाभिहित अधिकारी

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रति अग्रेषित की गई :

- (1) अध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (2) कोषाध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (3) संयुक्त सचिव (बैंककारी प्रशासक), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

**S.O. 2697(E).**— In exercise of the powers conferred by section 49 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) (Amendment) Rules, 2008.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendment of rule 2.- In the State Bank of India (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 2, -  
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely -  
'(aa) "Appellate Authority" means the Central Government or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour, Government of India, as the case may be;';  
(ii) in clause (c), for the words and bracket "Chief Labour Commissioner (Central)", the words "Designated Officer" shall be substituted.
3. Amendment of rule 3.- For rule 3 of the said rule, the following rule shall be substituted, namely, -  
'3. Nomination of workman employee director.- The director referred to in clause (e) of sub section (1) of section 19 of the Act shall be nominated by the Central Government from a panel of not less than three numbers of employees as furnished by the representative Union to the Bank, within a period of 30 days from the receipt of such panel:

Provided that on the request of the representative union, the Central Government may, at its direction, increase further period of 15 days to furnish the panel of names of employees to the Bank:

Provided further that in case the representative Union fails to furnish the panel of names of employees and does not send the same within the period as specified above, the Bank shall inform the Central Government, and, after receipt of information for the Bank, the Central Government may ask the Bank management to obtain a panel of three names of employees from the next largest Union:

Provided also that in case at any time, if the Central Government is of opinion that there is likely to be delay in the verification and certification of any Union, Federation or Association of the Bank, as a representative union and it is necessary in the interests of the State Bank so to do, it may nominate any employee of the State Bank of India, who is a workman, to be a director of that Bank."

4. Substitution of new Schedule for the First Schedule.- For the First Schedule of the said rule, the following Schedule shall be substituted, namely;

**'THE FIRST SCHEDULE'**

[See rule 2(c)]

**Subject: Procedure for verification of membership of Union operating in the State Bank.**

1. The management of the Bank shall be advised by the Central Government, one year before the expiry of the tenure of the incumbent workmen directors, to verify the membership strength of the workmen Union belonging to workman employee of the Bank for the purpose of determination of representative Union. The management of the Bank or the Chairman or Managing Director shall nominate an officer at the level of General Manager as the Designated Officer, who shall make the aforesaid verification. The verification of the membership of the Union, Federation or Association is to be done on the basis of the deduction made from the salary of the workmen for the month of March of the relevant year based on the check off mandate.

2. The data or detail, as the case may be, as per Annexure 1 shall be accompanied by list(s) showing the name of the members of each Union of workmen of the Bank, his or her designation and branch or office where he or she is working shall be compiled immediately on receipt the advise of the of the Central Government as referred to in Paragraph 1.

Explanation: For the purposes of this paragraph, a workman of the Bank shall be considered as a member of a particular Union, subject to the conditions, that, -

- (a) he can give only one check off mandate in favour of one particular Union at any given point of time; and
- (b) the Bank shall only reckon the membership status of workmen based on the check off mandate for the salary of month of March of the relevant year.

3. The Designated Officer shall, within a period of 7 days of receipt of communication from the Central Government regarding the representative Union lists showing the names of members of the Union forward the copy of the verification of membership as per Annexure – II to the Union, Federation or Association and call upon them to accept or object its authenticity, if any, within a period of 30 days from the date of receipt of the copy.

4. If no objection is received within a period of 30 days from the date of receipt of the copy of the verification of membership by the Designated Officer, it shall be presumed that there is no objection from the Union, Federation or Association and the Designated Officer shall proceed further accordingly.

5. The Union, Federation or Association shall not raise general or vague objection, and if the objection is general or vague, such objection shall not be considered. The Union, Federation or Association shall specifically state the name(s), designation(s), place of working of the workman in respect of whom objection is or are being raised and the reasons therefor.

6. If any objection is received from the Union, Federation or Association, the Designated Officer shall verify the same as to whether by reckoning the difference in the membership strength as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union having majority of the workmen in the Bank as its members and certified so by the Bank, shall get altered.

7. If by reckoning the difference in the membership strength, as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union certified to be representative Union changes, then the Designated Officer shall verify the relevant records as to the deduction of Union membership fees under the system of check off at Head Office, Corporate Office, Zonal Office or Regional Office of the Bank.

8. The Designated Officer may, for the purpose of the verification of the membership, appoint Verifying Officer(s) of the Bank, who is equivalent to the rank of Senior Manager or Chief Manager as the Verifying Officer. The Verifying Officer(s) shall verify the name objected by the contesting Union in the presence of the representatives of the Bank and the concerned Union. The Verifying Officer may enquire from the concerned employee(s) about his or their affiliation to one or any other Union. In the course of such personal enquiry by the Verifying Officer(s), no representative of any of the Union, Federation, Association or management of the Bank shall be present. After completion of the verification, the Verifying Officer(s) shall submit his report to the Designated Officer.

9. Subject to paragraph 8, the Designated Officer shall finalize the verification of membership of the Union and submit his report within a period of 7 days from the date of finalization of the verification to the Central Government through the Chairman or Managing Director or, in his absence through the Executive Director of the Bank. A copy of such report shall be sent to the representative Union and contesting Union, Federation or Association of the Bank.

10. An Appeal shall lie against the report of the Designated Officer before the Appellate Authority if the difference in membership contested or objected is more than 5% of the total workmen employee strength of the Bank or to change the status of the representative Union. Any Union, Federation or Association having objection to the status of representative Union as determined by the Designated Officer may file an appeal, giving reason in writing, within a period of 7 days from the date of issue of such report by the Designated Officer. The Appellate Authority shall, within a period of not more than 60 days from the date of filing of the Appeal either by conduct of inquiry or by perusal of records and giving an opportunity of being heard to the parties, pass an order in writing. A copy of such order shall be sent to both the parties to the Appeal. The Designated Officer shall modify the list on the basis of such order, and send the same to the Central Government within a period of 7 days from the date of the receipt of the order of the Appellate Authority.

11. Obtaining a panel from representative Union.— The Bank shall, within a period of 7 days from the date of receipt of the status report of the representative Union from the Designated Officer, ask the representative Union to furnish a panel of three names of the office bearers in order of preference for appointment of workmen director on the Bank's board under intimation to the Central Government. In case the representative Union fails to furnish the panel of names of the office bearers within a period of 30 days from the date of the receipt of such direction, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of the employees from the next largest Union within a period of 30 days:

Provided that on the request of the largest Union, the Central Government may increase further period of 15 days to furnish the panel of the names of employees of the Bank.

12. The representative Union or the next largest Union shall furnish panel of three names to the management of the Bank and send a copy of the same to the Central Government. The management of the Bank on receipt of the panel of names, shall send the following informations in respect of each of the persons in the panel to the Central Government,-

- (i) complete bio-data;
- (ii) copies of the Confidential reports for the last 5 years;

- (iii) certificate to the effect that no vigilance or disciplinary case is pending or being contemplated;
- (iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being nominated as director on the Bank's board as per the provisions of any law for the time being in force;
- (v) integrity and moral character certificate by the Bank's chief executive;
- (vi) composition of the present Board of Directors of the Bank;
- (vii) the data relating to credit, deposit and profit or loss for the last three years;
- (viii) confirmation regarding pendency of any case in any Court with regard to nomination of Workmen Employee Director on the Board of the Bank; and
- (ix) certificate from the Bank that there is no stay order which may prohibit the Central Government to nominate the Workmen Employee Director on the Board of the Bank.

Explanation.- For the purposes of this Schedule, the expression "check off" means a voluntary arrangement of collection of Union subscriptions from the members of a Union from the wages at source and passing off the money so deducted to the Union by the Bank and also the authorization to deduct from the wages which may indicate the consent to make the check off deduction and shall be signed with date.

[F. No. 15/5/2003-IR-(iii)]

K. V. EAPEN, Jt. Secy.

**Foot Note :** The State Bank of India (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide, S.O. 399 (E), dated the 29th June, 1974 Subsequently amended in 1976.



## ANNEXURE I

## Certificate of membership strength of workmen unions functioning in.....(Bank)

1. The total number of workmen employee employed in the Bank as on 31<sup>st</sup> March of the relevant year\_\_\_\_\_
2. The total number of workmen employee covered by the check off system:-
3. The membership strength of each Union of workmen employee in the bank based on check off mandate for the salary for the month of March of the relevant year, is as follows,-

Sl. No.	Name and address of the Union	Registration No. and date of Registration of the Union	Whether the Union is primary or federating unit	Affiliation		Name of the President, General Secretary, Treasurer of the Union with their postal addresses	Total membership in the bank as per check off mandate
				Central Organisation	State/All India Federation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the above information is true and correct as per records available in, and maintained by, the Bank.

Date:-

Designated Officer

Place:-

4592GI/af-6

## ANNEXURE II

First Notice by Regd. A.D.  
Second Notice

BANK  
(Head Office)

dated the....., 200

No.

To,

The General Secretary,

.....  
.....

**Subject:- Verification of membership of Union operating in State Bank of India.**

Dear Sir,

I am to invite the reference to the procedure for verification of membership of Union operating in the State Bank of India (copy enclosed) and I am enclosing herewith a detailed list of membership of Union based on the salary for the month of March of the relevant year, showing the names of each member, designation, branch or office where working, as provided by the bank based on the check off mandates given by the employee.

2. I request you to peruse the list and convey your acceptance thereof as to the correctness of the list, within 30 days from the date of receipt of this Annexure.

3. In case you have any objection to the presence or otherwise of an employee in the list, you may raise objection by stating your specific objections and forward it to the undersigned within a period of 30 days from the date of receipt of this Annexure. Please note that you shall not raise any general or vague objections like inflated membership and the objection should give names of persons whose membership to the Union is not reflected in the list as also the names of persons whose membership in the Union is objected to and the reason therefor.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Designated Officer

Copy forwarded for information to:-

- (1) The President ..... (Name and address of the Union)
- (2) The Treasurer ..... (Name and address of the Union)
- (3) Joint Secretary (Banking Administration), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 2698(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन- समनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,—

(i) उपनियम (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(स्तक) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है ;”;

(ii) उपनियम (ख) में, “मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “पदाभिहित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

3. नियम 3 का संशोधन- उक्त नियम के नियम 3 में, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. कर्मकार कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति- अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (गक) में निर्दिष्ट निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन से अन्यून कर्मचारियों के ऐसे पैनल से, जो प्रतिनिधि संघ द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे पैनल की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रतिनिधि संघ के अनुरोध पर, स्वविवेकानुसार, बैंक के लिए कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने के लिए अवधि को 15 दिन के लिए और बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रतिनिधि संघ कर्मचारियों के नामों की सूची प्रस्तुत करने में असफल रहता है और ऊपर यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसको नहीं भेजता है तो बैंक केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और बैंक से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, बैंक के प्रबंधन से अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों का पैनल अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी प्रतिनिधि संघ के रूप में बैंक के किसी संघ, परिसंघ, संगम के सत्यापन या प्रमाणीकरण में विलंब होने की संभावना है और किसी समनुषंगी बैंक के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह समनुषंगी बैंक के किसी कर्मचारी को जो कोई कर्मकार है उस बैंक के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।”;

4. प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन किया जाना- उक्त नियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

**‘पहली अनुसूची**  
**[खंड 2(घ) देखिए]**

**विषय : समनुषंगी बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया ।**

1. पदधारी कर्मकार निदेशकों के कार्यकाल के अवसान से एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार बैंक के प्रबंधन को, प्रतिनिधि संघ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बैंक के कर्मकार कर्मचारी से संबंधित संघ की सदस्यता की पदसंख्या का सत्यापन करने की सलाह देगी । बैंक का प्रबंधन या प्रबंध निदेशक या मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के किसी अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो पूर्वोक्त सत्यापन करेगा । संघ, परिसंघ या संगम की सदस्यता का सत्यापन चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित सुसंगत वर्ष के मार्च मास के लिए कर्मकार के वेतन से की गई कटौती के आधार पर किया जाना है ।

2. उपाबंध 1 के अनुसार, यथास्थिति, आंकड़ों या व्यौरों के साथ सूची (सूचियाँ) संलग्न होगी, जिनमें बैंक के कर्मकारों के प्रत्येक संघ के सदस्यों के नाम, उसका पदनाम और उसके कार्यकरण की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया जाएगा, ऐसी सूची (सूचियाँ) को पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार की सलाह की प्राप्ति पर तुरंत संकलित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण** — इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए, बैंक के किसी कर्मकार को किसी विशिष्ट संघ के सदस्य के रूप में माना जाएगा, कि, —

(क) वह किसी भी दिए गए समय पर किसी विशिष्ट संघ के पक्ष में केवल एक चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र दे सकता है ; और

(ख) बैंक केवल सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन के लिए चंदा कटौती संबंधी अधिकार पत्र पर आधारित कर्मकार की सदस्यता प्राप्ति को गणना में लेगा।

3. पदाभिहित अधिकारी, संघ के सदस्यों के नामों को दर्शित करने वाली प्रतिनिधि संघ सूची के संबंध में केंद्रीय सरकार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, संघ, परिसंघ या संगम को उपाबंध-2 के अनुसार सदस्यता के सत्यापन की एक प्रति अग्रेषित करेगा और उनसे यह मांग करेगा कि वे ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करें या उनके प्रति कोई आक्षेप, यदि कोई हों, करें।

4. यदि पदाभिहित अधिकारी को सदस्यता के सत्यापन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संघ, परिसंघ या संगम का कोई आक्षेप नहीं है और पदाभिहित अधिकारी तदनुसार आगे कार्यवाही करेगा।

5. संघ, परिसंघ या संगम कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं करेंगे और यदि आक्षेप साधारण या अस्पष्ट है तो ऐसे आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ, परिसंघ या संगम विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे कर्मकार के, जिसके संबंध में आक्षेप किया/किए जा रहे हैं, नाम (नामों), पदनाम (पदनामों), कार्यकरण के स्थान का विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेंगे और आक्षेप के कारणों का भी कथन करेंगे।

6. यदि संघ, परिसंघ या संगम से कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो पदाभिहित अधिकारी उसका इस संबंध में सत्यापन करेगा कि क्या संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, बैंक में कर्मकारों की बहुसंख्या को उसके सदस्यों के रूप में रखने वाले संघ की प्राप्ति जिसे बैंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, परिवर्तित हो जाएगी।

7. यदि संघ, परिसंघ या संगम द्वारा उसके आक्षेप में यथाकथित सदस्यों की संख्या में अंतर को गणना में लेते हुए, प्रतिनिधि संघ के रूप में प्रमाणित संघ की प्राप्ति में परिवर्तन होता है तब पदाभिहित अधिकारी बैंक के प्रधान कार्यालय, निगम कार्यालय, जोनल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय पर चंदा कटौती की प्रणाली के अधीन संघ सदस्यता फीस की कटौती के संबंध में सुसंगत अभिलेखों का सत्यापन करेगा।

8. पदाभिहित अधिकारी, सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए बैंक के सत्यापन अधिकारी (अधिकारियों) को नियुक्त कर सकेगा, जो सत्यापन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ प्रबंधक या मुख्य

प्रबंधक की रैंक के समतुल्य होंगे। सत्यापन अधिकारी बैंक और संबंधित संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले संघ द्वारा आक्षेप किए गए नाम का सत्यापन करेगा (करेंगे)। सत्यापन अधिकारी संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों से उसके या उनके किसी एक या किसी अन्य संघ से संबंध के बारे में पूछताछ कर सकेगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ऐसी व्यक्तिगत पूछताछ के अनुक्रम में, संघ, परिसंघ, संगम या बैंक के प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा। सत्यापन के पूरा होने के पश्चात्, सत्यापन अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।

9. पैरा 8 के अधीन रहते हुए पदाभिहित अधिकारी संघ की सदस्यता के सत्यापन को अंतिम रूप देगा और सत्यापन को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या, उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक के माध्यम से केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बैंक के प्रतिनिधि संघ और निर्वाचन लड़ने वाले संघ, परिसंघ या संगम को भी भेजी जाएगी।

10. यदि विवादास्पद या आक्षेप की गई सदस्यता में अंतर बैंक के कुल कर्मकार कर्मचारिवृंद की संख्या के 5% से अधिक है या प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति को परिवर्तित करने वाला है तो पदाभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकेगी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित प्रतिनिधि संघ की प्रास्थिति के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई संघ, परिसंघ या संगम, पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट को जारी करने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए अपील फाइल कर सकेगा। अपील प्राधिकरण, या तो जांच का संचालन करके या अभिलेखों का अवलोकन करके तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अनधिक अवधि के भीतर लिखित में एक आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश की एक प्रति अपील के दोनों पक्षों को भेजी जाएगी। पदाभिहित अधिकारी ऐसे आदेश के आधार पर सूची को उपांतरित करेगा और अपील प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उसे केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

11. प्रतिनिधि संघ से एक पैनल प्राप्त करना — बैंक, पदाभिहित अधिकारी से प्रतिनिधि संघ से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार को संसूचित करते हुए प्रतिनिधि संघ को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिमानतः के क्रम में पदधारियों के तीन नामों का एक पैनल प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि प्रतिनिधि संघ, ऐसे निदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पदधारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बैंक केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा और केंद्रीय सरकार सूचना की प्राप्ति के पश्चात् बैंक के प्रबंधन को 30 दिन की अवधि के भीतर अगले सबसे बड़े संघ से कर्मचारियों के तीन नामों के पैनल को अभिप्राप्त करने के लिए कह सकेगी :

परंतु सबसे बड़े संघ के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार बैंक के कर्मचारियों के नामों के पैनल को प्रस्तुत करने की अवधि में 15 दिन की और वृद्धि कर सकेगी।

12. प्रतिनिधि संघ या अगला सबसे बड़ा संघ बैंक के प्रबंधन को तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। बैंक का प्रबंधन, नामों का पैनल प्राप्त होने

पर, केंद्रीय सरकार को पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं भेजेगा, —

- (i) पूर्ण बायो-डाटा ;
- (ii) पिछले पांच वर्ष की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां ;
- (iii) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है या अनुध्यात नहीं किया जा रहा है ;
- (iv) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि वे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरहिंत नहीं हैं ;
- (v) बैंक के मुख्य कार्यपालक से सत्यता और नैतिक चरित्र का प्रमाणपत्र ;
- (vi) बैंक के विद्यमान निदेशक बोर्ड की संरचना ;
- (vii) पिछले तीन वर्षों के क्रेडिट, निक्षेप और लाभ या हानि से संबंधित आंकड़े ;
- (viii) बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक के नामनिर्देशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी मामले के लंबित होने के संबंध में पुष्टिकरण ; और
- (ix) बैंक से यह प्रमाणपत्र कि ऐसा कोई स्थगनादेश नहीं है जो केंद्रीय सरकार को बैंक के बोर्ड पर कर्मकार कर्मचारी निदेशक को नामनिर्देशित करने से प्रतिषिद्ध करें ।

स्पष्टीकरण — इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, “चंदा कटौती” अभिव्यक्ति से किसी संघ के सदस्यों से संघ संबंधी अभिदायों के स्रोत पर मजदूरियों से संग्रहण करने और इस प्रकार कटौती किए गए धन को बैंक द्वारा संघ को अंतरित करने और साथ ही मजदूरियों में से कटौती करने का प्राधिकार देने का भी, जिसमें चंदा कटौती करने की सहमति उपदर्शित हो सकेगी तथा जिस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे, स्वीच्छिक कन्सर अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 15/5/2003-आई. आर.-(iv)]

के. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** समनुषंगी बैंक (कर्मचारी निदेशक नियुक्ति) नियम, 1974 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग (ii), खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) तारीख 29 जून, 1974 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 1976 में संशोधित किया गया था ।

## उपाबंध 1

..... (बैंक) में कार्यरत कर्मकार संघों की सदस्यता संख्या का प्रमाणपत्र

1. सुसंगत वर्ष ..... की 31वीं मार्च को बैंक में नियोजित कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
2. चंदा कटौती प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मकार कर्मचारियों की कुल संख्या ;
3. सुसंगत वर्ष के मार्च मास के वेतन से चंदा कटौती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक में कर्मकार कर्मचारियों के प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	संघ का नाम और पता	संघ का रजिस्ट्रीकरण सं. और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या संघ प्राथमिक है अथवा परिसंघीय ईकाई है	संबंधन		संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के नाम, उनके डाक पत्तों सहित	चंदा कटौती अधिकार पत्र के अनुसार बैंक में सदस्यों की कुल संख्या
				केंद्रीय संगठन	राज्य/अखिल भारतीय परिसंघ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी बैंक में उपलब्ध तथा उसके द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

तारीख :

स्थान :

पदाभिहित अधिकारी



## उपबन्ध 2

रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति के साथ प्रथम सूचना

द्वितीय सूचना

बैंक

(प्रधान कार्यालय)

तारीख ....., 200

सं.

सेवा में,

महासचिव,

.....

.....

**विषय : समनुषंगी बैंक में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता का सत्यापन ।**

प्रिय महोदय,

मैं समनुषंगी बैंकों में प्रचालन कर रहे संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ (प्रति संलग्न है) और मैं इसके साथ सुसंगत वर्ष के मार्च मास के बैलन के आधार पर संघ के सदस्यों की एक व्यवस्थित सूची संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें कर्मचारी द्वारा दिए गए चंदा कटीती अधिकार पत्र के आधार पर बैंक द्वारा उपलब्ध कसए गए प्रत्येक सदस्य के नाम, पदनाम, कार्य करने की शाखा या कार्यालय को दर्शित किया गया है ।

2. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सूची का अवलोकन करें और इस उपबन्ध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर सूची के सही होने के संबंध में अपनी स्वीकृति संश्लेषित करें ।

3. यदि आपको सूची में किसी कर्मचारी के उपस्थित होने या अन्यथा के संबंध में कोई आक्षेप है, तो आप अपने विनिर्दिष्ट आक्षेपों का कथन करते हुए आक्षेप कर सकते हैं और इस उपबन्ध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकते हैं । कृपया यह नोट करें कि आप बड़ी हुई सदस्यता जैसे कोई साधारण या अस्पष्ट आक्षेप नहीं उठाएँ और आक्षेप में ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए, जिनकी संघ के सदस्य होने की बात सूची में दर्शित नहीं की गई है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के नाम भी दिए जाने चाहिए जिनके संघ के सदस्य होने के प्रति आक्षेप किया गया है और उसके कारण भी दिए जाने चाहिए ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करें ।

भवदीय,

पदाभिहित अधिकारी

निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रति अग्रेषित की गई :

- (1) अध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (2) कोषाध्यक्ष ..... (संघ का नाम और पता)
- (3) संयुक्त सचिव (बैंककारी प्रशासक), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

**S.O. 2698(E).**— In exercise of the powers conferred by section 62 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.- In the Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 2,-

(i) after sub-rule (b), the following sub-rule shall be inserted, namely, -

'(ba) "Appellate Authority" means the Central Government or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour, Government of India, as the case may be;'

(ii) in sub-rule (d), for the words and bracket "Chief Labour Commissioner (Central)", the words "Designated Officer" may be substituted.

3. Amendment of rule 3.- For rule 3 of the said rule, the following rule shall be substituted, namely,-

3. Nomination of workmen employee director.- The director referred to in clause (ca) of sub section (1) of section 25 of the Act shall be appointed by the Central Government from a panel of not less than three employees as furnished by the representative Union to the Bank, within a period of 30 days from the receipt of such panel:

Provided that on the request of the representative union, the Central Government may, at its direction, increase further period of 15 days to furnish the panel of names of employees to the Bank:

Provided further that in case the representative Union fails to furnish the panel of names of employees and does not send the same within the period as specified above, the Bank shall inform the Central Government, and after receipt of information from the Bank, the Central Government may ask the Bank management to obtain a panel of three names of employees from the next largest Union.

Provided also that in case at any time, if the Central Government is of opinion that there is likely to be delay in the verification and certification of any Union, Federation or Association of the Bank, as a representative Union and it is necessary in the interests of a subsidiary Bank so to do, it may nominate any employee of the Subsidiary Bank, who is a workman, to be a director of that Bank.

4. Substitution of new Schedule for the First Schedule.- For the First Schedule of the said rule, the following shall be substituted, namely:-

#### THE FIRST SCHEDULE

[See rule 2(d)]

**Subject :** Procedure for verification of membership of Union operating in the Subsidiary Bank.

1. The management of the Bank shall be advised by the Central Government, one year before the expiry of the tenure of the incumbent workmen directors, to verify the membership strength of the workmen Union belonging to workman employee of the Bank for the purpose of determination of representative Union. The management of the Bank or the Managing Director or Chief General Manager shall nominate an officer at the level of General Manager as the Designated Officer, who shall make the aforesaid verifications. The verification of the membership of the Union, Federation or Association is to be done on the basis of the deduction made from the salary of the workmen for the month of March of the relevant year, based on the check off mandate. The term check off is defined as under:

2. The data or detail, as the case may be, as per Annexure 1 shall be accompanied by list(s) showing the name of the members of each Union of workmen of the Bank, his or her designation and branch of office where he or she is working shall be compiled immediately on receipt of the advice of the Central Government communication as referred to in Paragraph 1.

Explanation: For the purposes of this paragraph, a workman of the Bank shall be considered as a member of a particular Union, subject to the conditions, that, -

- (a) he can give only one check off mandate in favour of one particular Union at any given point of time; and
- (b) the Bank shall only reckon the membership status of workmen based on the check off mandate for the salary of month of March of the relevant year.

3. The Designated Officer shall, within a period of 7 days of receipt of communication from the Central Government regarding the representative Union lists showing the names of members of the Union forward the copy of the verification of membership as per Annexure – II to the Union, Federation or Association and call upon them to accept or object its authenticity, if any, within a period of 30 days from the date of receipt of the copy.

4. If no objection is received within a period of 30 days from the date of receipt of the copy of the verification of membership by the Designated Officer, it shall be presumed that there is no objection from the Union, Federation or Association and the Designated Officer shall proceed further accordingly.

5. The Union, Federation or Association shall not raise general or vague objection, and if the objection is general or vague, such objection shall not be considered. The Union, Federation or Association shall specifically state the name(s), designation(s), place of working of the workman in respect of whom objection is or are being raised and the reasons therefor.

6. If any objection is received from the Union, Federation or Association, the Designated Officer shall verify the same as to whether by reckoning the difference in the membership strength as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union having majority of the workmen in the Bank as its members and certified so by the Bank, shall get altered.

7. If by reckoning the difference in the membership strength, as stated by the Union, Federation or Association in its objection, the status of the Union certified to be representative Union changes, then the Designated Officer shall verify the relevant records as to the deduction of Union membership fees under the system of check off at Head Office, Corporate Office, Zonal Office or Regional Office of the Bank.

8. The Designated Officer may, for the purpose of the verification of the membership, appoint Verifying Officer(s) of the Bank, who is equivalent to the rank of Senior Manager or Chief Manager as the Verifying Officer. The Verifying Officer(s) shall verify the name objected by the contesting Union in the presence of the representatives of the Bank and the concerned Union. The Verifying Officer may enquire from the concerned employee(s) about his or their affiliation to one or any other Union. In the course of such personal enquiry by the Verifying Officer(s), no representative of any of the Union, Federation, Association or management of the Bank shall be present. After completion of the verification, the Verifying Officer(s) shall submit his report to the Designated Officer.

9 Subject to paragraph 8, the Designated Officer shall finalize the verification of membership of the Union and submit his report within a period of 7 days from the date of finalization of the verification to the Central Government through the Chairman or Managing Director or, in his absence through the Executive Director of the Bank. A copy of such report shall be sent to the representative Union and contesting Union, Federation or Association of the Bank.

10. An Appeal shall lie against the report of the Designated Officer before the Appellate Authority if the difference in membership contested or objected is more than 5% of the total workmen employee strength of the Bank or to change the status of the representative Union. Any Union, Federation or Association having objection to the status of representative Union as determined by the Designated Officer may file an appeal, giving reason in writing, within a period of 7 days from the date of issue of such report by the Designated Officer. The Appellate Authority shall, within a period of not more than 60 days from the date of filing of the Appeal either by conduct of inquiry or by perusal of records and giving an opportunity of being heard to the parties, pass an order in writing. A copy of such order shall be sent to both the parties to the Appeal. The Designated Officer shall modify the list on the basis of such order, and send the same to the Central Government within a period of 7 days from the date of the receipt of the order of the Appellate Authority.

11. Obtaining a panel from representative Union.— The Bank shall, within a period of 7 days from the date of receipt of the status report of the representative Union from the Designated Officer, ask the representative Union to furnish a panel of three names of the office bearers in order of preference for appointment of workmen director on the Bank's board under intimation to the Central Government. In case the representative Union fails to furnish the panel of names of the office bearers within a period of 30 days from the date of the receipt of such direction, the Bank shall inform the Central Government and, after receipt of information, the Central Government may ask the management of the Bank to obtain a panel of three names of the employees from the next largest Union within a period of 30 days:

Provided that on the request of the largest Union, the Central Government may increase further period of 15 days to furnish the panel of the names of employees of the Bank.

12. The representative Union or the next largest Union shall furnish panel of three names to the management of the Bank and send a copy of the same to the Central Government. The management of the Bank on receipt of the panel of names, shall send the following information in respect of each of the persons in the panel to the Central Government,-

- (i) complete bio-data;
- (ii) copies of the Confidential reports for the last 5 years;

- (iii) certificate to the effect that no vigilance or disciplinary case is pending or being contemplated;
- (iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being nominated as director on the Bank's board as per the provisions of any law for the time being in force;
- (v) integrity and moral character certificate by the Bank's chief executive;
- (vi) composition of the present Board of Directors of the Bank;
- (vii) the data relating to credit, deposit and profit or loss for the last three years;
- (viii) confirmation regarding pendency of any case in any Court with regard to nomination of Workmen Employee Director on the Board of the Bank; and
- (ix) certificate from the Bank that there is no stay order which may prohibit the Central Government to nominate the Workmen Employee Director on the Board of the Bank.

Explanation.- For the purposes of this Schedule, the expression "check off" means a voluntary arrangement of collection of Union subscriptions from the members of a Union from the wages at source and passing off the money so deducted to the Union by the Bank and also the authorization to deduct from the wages which may indicate the consent to make the check off deduction and shall be signed with date.

[F. No. 15/5/2003-IR-(iv)]  
K. V. EAPEN, Jt. Secy.

**Foot Note :** The Subsidiary Banks (Appointment of Employee Directors) Rules, 1974 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide, S.O. 399 (E), dated the 29th June, 1974 Subsequently amended in 1976.

## ANNEXURE I

**Certificate of membership strength of workmen unions functioning in.....(Bank)**

1. The total number of workmen employee employed in the Bank as on 31<sup>st</sup> March of the relevant year\_\_\_\_\_
2. The total number of workmen employee covered by the check off system:-
3. The membership strength of each Union of workmen employee in the bank based on check off mandate for the salary for the month of March of the relevant year, is as follows,-

Sl. No.	Name and address of the Union	Registration No. and date of Registration of the Union	Whether the Union is primary or federating unit	Affiliation		Name of the President, General Secretary, Treasurer of the Union with their postal addresses	Total membership in the bank as per check off mandate
				Central Organisation	State/All India Federation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the above information is true and correct as per records available in, and maintained by, the Bank.

Date:-

Designated Officer

Place:-

## ANNEXURE II

First Notice by Regd. A.D.  
Second Notice

BANK  
 (Head Office)

dated the....., 200

No.

To,

The General Secretary,

.....  
 .....

**Subject:- Verification of membership of Union operating in Subsidiary Bank.**

Dear Sir,

I am to invite the reference to the procedure for verification of membership of Union operating in the Subsidiary Banks (copy enclosed) and I am enclosing herewith a detailed list of membership of Union based on the salary for the month of March of the relevant year, showing the names of each member, designation, branch or office where working, as provided by the bank based on the check off mandates given by the employee.

2. I request you to peruse the list and convey your acceptance thereof as to the correctness of the list, within 30 days from the date of receipt of this Annexure.

3. In case you have any objection to the presence or otherwise of an employee in the list, you may raise objection by stating your specific objections and forward it to the undersigned within a period of 30 days from the date of receipt of this Annexure. Please note that you shall not raise any general or vague objections like inflated membership and the objection should give names of persons whose membership to the Union is not reflected in the list as also the names of persons whose membership in the Union is objected to and the reason therefor.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Designated Officer

Copy forwarded for information to:-

- (1) The President ..... (Name and address of the Union)
- (2) The Treasurer .....(Name and address of the Union)
- (3) Joint Secretary (Banking Administration), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.